

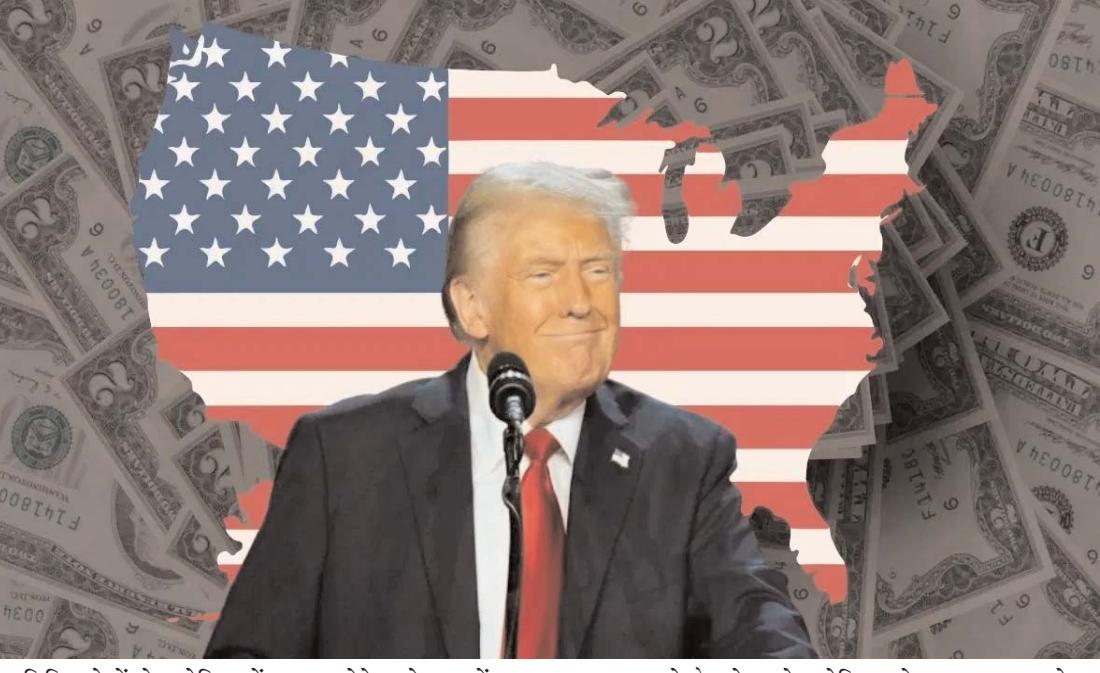
विचार

भारत का महा आर्थिक संकट, शेयर बाजार और बैंकों में हाहाकार

भारत में आर्थिक मंदी जिस तरह से सामने आ रही है। जिसमें अर्थतंत्र के सारे संस्थान डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर बाजार में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट को थामने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने लाखों करोड़ रुपया शेयर बाजार में डाला। वह रुपया भी मुनाफा वसूली में शेयर बाजार से बाहर निकल गया। रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में डिविडेंड के नाम पर काफी बड़ी राशि वसूल कर की है। जिसके कारण रिजर्व बैंक का आर्थिक संकट भी सामने दिख रहा है। रही सही कसर सरकारी बैंक पूरी कर रहे हैं। बैंकों द्वारा जो फाइनेंस किया गया है। उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। बैंकों द्वारा पिछले वर्षों में खातेदारों से तरह-तरह के शुल्क लगाकर अनाप-शानाप वसूली की जा रही है। एनपीए खाते की रकम का समयोजन कर बैंकों का मुनाफा बैलेंस शीट में लाभ से एडजस्ट किया जा रहा है। पिछले वर्षों में शेयर बाजार में बैंकों द्वारा भारी निवेश किया गया है। जब तक शेयर बाजार में तेजी बनी हुई थी। तब तक बैंकों की बैलेंस शीट मुनाफा उगल रही थी। अब बैंकों की बैलेंस शीट घटे की ओर आगे बढ़ रही हैं। जीवन बीमा निगम जैसी कंपनियां लड़खड़ा रही हैं। म्युचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान भी शेयर बाजार की गिरावट के कारण आर्थिक हालत खराब होती चली जा रही है। भारत के करोड़ों परिवार कर्ज के जाल में फँसे हुए हैं ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है। उसके अनुसार 68 फीसदी कर्जदारों को ईएमआई चुकाने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 45 अरब डॉलर का कर्ज फंसा हुआ है। 91 से 180 दिनों के भीतर लोन की किस्त जमा नहीं होने पर बैंक यह राशि एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए 3.3 फीसदी की रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। 2023 में यह आंकड़ा मात्र 0.8 फीसदी था। भारत में लोन चुकाने के लिए अब लोग लोन ले रहे हैं। आर्थिक संकट के कारण लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकालना पड़ रहा है। बैंकों में लोन डिफाल्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस के तहत बड़ी मात्रा में पर्सनल ब्रैश दिया गया है। इस ब्रैश की भी वसूली नहीं हो पा रही है। 10 में से 9 लोगों के पास औपचारिक और स्थाई नौकरी नहीं है। जिसके कारण वह लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। समूह लोन जो दिया गया था, वह भी वसूल नहीं हो पा रहा है। माइक्रो फाइनेंस के लोन की किस्तें भी लोग नहीं चुका पा रहे हैं। लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं है, उनकी मासिक खर्च लायक आमदनी नहीं है।

टैरिफ युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा अधिक प्रभाव

दिनांक 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डॉनल्ड ट्रप द्वारा, विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयातित उत्पादों पर की गई टैरिफ सबंधी घोषणा के साथ ही अंततः अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में टैरिफ के माध्यम से व्यापार युद्ध छेड़ दिया गया है। अभी, अमेरिका ने विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर विभिन्न दरों पर टैरिफ लगाया है। अब इनमें से कई देश अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं, जैसे चीन ने अमेरिका से चीन में आयात होने वाले उत्पादों पर दिनांक 10 अप्रैल 2025 से 34 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है। टैरिफ के माध्यम से छेड़ गए व्यापार युद्ध का भारत पर कोई बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ने की सभावना बैंक ही है। दरअसल, अमेरिका ने विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है और साथ ही कुछ उत्पादों के आयात पर टैरिफ की गई है। टैरिफ की यह दरें 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।



विभिन्न देशों से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। साथ ही, कछ अन्य देशों वथा चीन से आयातित उत्पादों पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। इसी प्रकार, वित्तीय उत्पादन पर 46 प्रतिशत, ताइवान पर 32 प्रतिशत, थाईलैंड पर 36 प्रतिशत, भारत पर 26 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड पर 31 प्रतिशत, मलेशिया पर 24 प्रतिशत, कम्बोडिया पर 49 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका पर 30 प्रतिशत, बांगलादेश पर 37 प्रतिशत, पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत, श्रीलंका पर 40 प्रतिशत और इंडीया की राष्ट्रपति ने की है। अमेरिका का उत्पादन नहीं जाएगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए टैरिफ का बोझ अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की आयोगीया वस्तुओं को उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो एवं उन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अम

